



## GENERAL STUDIES (Module – 5)

निर्धारित समय: तीन घंटे  
Time allowed: Three Hours

DTVF/19 (N-M)-M-GS15

अधिकतम अंक: 250  
Maximum Marks: 250

Name: Alok Prasad

Mobile Number: \_\_\_\_\_

Medium (English/Hindi): Hindi

Reg. Number: 7100 (Anake)

Center & Date: MKN

UPSC Roll No. (If allotted): 5907765

### प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:  
इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।  
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

### QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

**Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:**

There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्ता द्वारा भरा जाए (To be filled by Evaluator only)

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्ता (हस्ताक्षर)  
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्ता (हस्ताक्षर)  
Reviewer (Signature)

1. भारत में रसद (लॉजिस्टिक्स) क्षेत्र को कौन-सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? हाल के दिनों में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये किये गए उपायों को गिनाइये। (150 शब्द) 10

What are the challenges facing the logistics sector in India? Enumerate the measures taken in recent times for giving a boost to this sector. (150 words) 10

लॉजिस्टिक्स से तात्पर्य किसी वस्तु के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लाने, ले जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया जिसमें परिवहन, माल चढ़ाना, माल उतारना, कस्टम क्लियरेंस, भण्डारण इत्यादि क्षेत्र सम्मिलित होते हैं।

भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में चुनौतियाँ

- 1) भारत में लॉजिस्टिक्स डेफ़ा की स्थिति काफी उपरीय है। सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा मात्र 2% है।
- 2) चीन की तुलना में भारत की लॉजिस्टिक्स लागत 5 गुना अधिक है। जिसके परिणामस्वरूप भारत की प्रतिस्पर्धामुक्तिता घटती है। और नियति कम होता है।
- 3) भारत में उच्चतम गुणवत्ता के बंदरगाह के अभाव के चलते भारत को

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

भारी सामान उतारने हेतु श्र्लिका ✓  
सिंगापुर के बंदरगाहों पर निर्भर रहना  
पड़ता है।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

4) आपात - निपति में कस्टम क्लिरेन्स  
हेतु सिंगल विंडो सिस्टम का अभाव

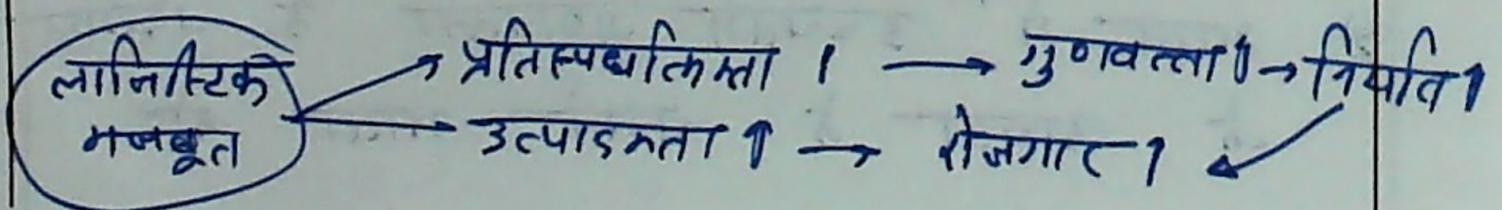
हाल के दिनों में सरकार लाजिस्टिक क्षेत्र  
को मजबूत करने का प्रयास कर  
रही है।

1) लाजिस्टिक क्षेत्र को अवसंरचना का स्वी  
रिया गया है।

2) सड़क परिवहन को तीव्रता से बढ़ाया  
जा रहा है। भारत में प्रतिदिन 25 KM  
सड़क निर्माण हो रहा है।

3) भारत माला परियोजना एवं सागर  
माला परियोजना के माध्यम से  
अवसंरचना विकास

लाजिस्टिक क्षेत्र भारत के उद्योगों की  
प्रतिस्पर्धकता  
बढ़ाने, एवं उनकी उत्पादकता बढ़ाने  
हेतु आवश्यक है।



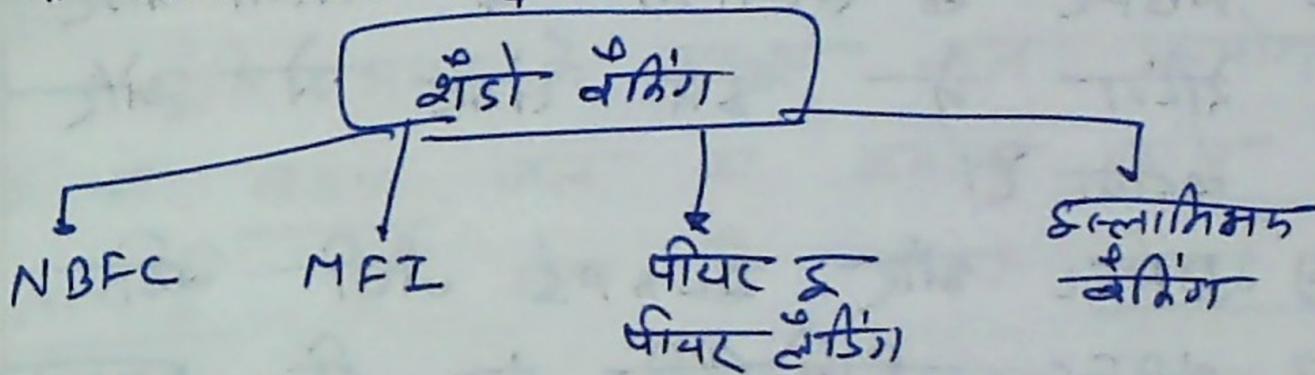
2. शैडो बैंकिंग प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है? वर्तमान में भारत की शैडो बैंकिंग प्रणाली को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? (150 शब्द) 10

What do you mean by shadow banking system? What are the challenges faced by India's shadow banking system at present? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

शैडो बैंकिंग प्रणाली मूल बैंकिंग प्रणाली से इतर वित्तीय व्यवस्था है। ध्यान रखें कि मूल बैंकिंग प्रणाली बैंकिंग अधिनियम 1949 एवं RBI अधिनियम - 1934 से संचालित होती है।



वर्तमान में ~~शैडो~~ बैंकिंग प्रणाली में धीमापन के साथ बढते NPA के कारण शैडो बैंकिंग का प्रचलन बढ़ा है। उदाहरण हेतु वाणिज्यिक बैंकों के ऋण प्रदान करने में मात्र 2% की गृही हुई वहीं NBFC द्वारा प्रदत्त ऋण में 15% के करीब गृही हुई हैं।

पुनर्निर्माण

- 1) NPA का संकट शॉर्टे बैंकिंग 2011 की या भी बड़ा है। उदाहरण हेतु पिछले 9 महीने में जहाँ वाणिज्यिक बैंकों के NPA में कमी आयी है वहीं NBFC का NPA 6.1% से बढ़कर 6.6% हो गया है।
- 2) NBFC ~~के~~ संस्थाओं का गलत क्रेडिट रेटिंग ने इस संकट में और बढ़ाया है।
- 3) DHFL और IL&FS जैसी बड़ी NBFC निष्पत्ति बंच की समस्या का सामना कर रही है।
- 4) पीपल टू पीपल बैंकिंग, NFI, इत्यादि में ~~प्र~~ प्रण की बाजार का ज्यादा होना।

सारंशतः बैंकिंग प्रणाली का अजडूत होना अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण प्रगति हेतु आवश्यक है। फलतः शॉर्टे बैंकिंग संबंधी पुनर्निर्माण को कम करने की आवश्यकता है।

3. भूमि उत्पादकता की बजाय सिंचाई जल उत्पादकता को प्राथमिकता देने की अपनी कुछ चुनौतियाँ हैं, जिन पर वर्तमान में ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Shifting of priority from land productivity to irrigation water productivity has its own set of challenges which need to be addressed in time. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में  
जल संकट की भावी रूपरेखा के चर्चे  
जल के बुद्धिमतापूर्ण उपयोग की  
ओर सभी का ध्यान आकृष्ट हुआ  
है।

चूंकि भारत के सम्पूर्ण जल उपयोग  
में से 89% जल का प्रयोग कृषि  
सिंचाई में होता है अतः सिंचाई  
जल उत्पादना का महत्व बढ़ा है।

हरित क्रांति के बाद से ही हमने  
खाद्य उत्पादन बढ़ाने हेतु

पर अत्यधिक ध्यान दिया

अच्छे बीज

सिन्सडी  
युक्त  
उर्वरक

सिंचाई  
इत्यादि  
की बिजली

किन्तु वर्तमान में सिंचाई जल उत्पादना  
को बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि

इसके अनेक नाम हैं

- 1) सूक्ष्म सिंचाई तकनीक के कारण उत्पादकता में 46% तक की वृद्धि
- 2) उर्वरकों की खपत काफी कम हो जाती है
- 3) किसानों की आय में 50% से अधिक वृद्धि

किन्तु इसके अनेक चुनौतियाँ भी शामिल हैं

- 1) भारत में मात्र 6% क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई से सिंचित है
- 2) वर्षा सिंचित क्षेत्र अभी भी 60% से अधिक बना हुआ है
- 3) सूक्ष्म सिंचाई की अत्यधिक लागत बड़ी समस्या है
- 4) बजटों की चरकी साइज (1008 हेक्टेयर) इसके आँट मुश्किल बनाता है

सरकार के कदम

- 1) सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई हेतु लगभग 3000 करोड़ का समर्पित फंड मिशन किया
- 2) प्रॉप ड्रॉप मोड काप के तहत बचावा
- 3) इजरायल से सहयोग लिया जा रहा है

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।  
(Candidate must not  
write on this margin)

4. मॉडल कृषि भूमि पट्टेदारी अधिनियम 2016 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? यह भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में कैसे सहायता प्रदान कर सकता है? (150 शब्द) 10

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

What are the key provisions of Model Agricultural Land Leasing Act 2016? How it can help in enhancing farm productivity in India? (150 words) 10

कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु कई समितियाँ  
(जैसे जयराज रमेश समिति) द्वारा लैंड  
लीजिंग एक्ट बनाने की अनुशंसा की  
गयी थी।

प्रावधान

- 1) भूमि स्वामी अपनी भूमि को निश्चित समय हेतु कालतकार को दे सकेगा। बदले में कालतकार स्वामी को भूमि मिराया देगा
- 2) भूमि स्वामी का भूमि पर कानूनी स्वामित्व बना रहेगा।

लैंड लीजिंग एक्ट के रिपॉन्स से कृषि उत्पादकता बढ़ाने में निम्न प्रकार से मदद मिलेगी।

- 1) कालतकार किसान अनुबंधित समय तक निश्चित होकर बेटी कर सकेगा फलतः वह निवेश करने में

अधिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा जिससे  
कृषि उत्पादकता बढ़ेगी।

2) लैंड लीजिंग पर दोटे जोत की  
समस्या का निराकरण करके  
सकता है। ~~किससे~~ जिससे उत्पादकता  
बढ़ेगी।

3) चूंकि भू-स्वामी का अनुबंधित  
जम्मेदार के अनुसार भूमि का  
मिथाया मिलेगा फलतः कारगर  
अधिक से अधिक लाभ कमाने  
हेतु भूमि उत्पादकता बढ़ाने का  
प्रयास होगा।

भारत की बढ़ती जनसंख्या और  
कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव कृषि  
उत्पादकता को बढ़ाने हेतु अति  
आवश्यक है। फलतः हमें लैंड  
लीजिंग के साथ साथ सहायी  
कृषि, चक्रवर्ती इत्यादि अन्य साधनों  
का भी उपयोग करना चाहिए।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

5. भारत के पहले मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम 'गगनयान' के उद्देश्यों और महत्व की चर्चा कीजिये। साथ ही उन महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का भी विस्तृत वर्णन कीजिये जिन्हें भारत ने 'गगनयान' के लिये विकसित किया है। (150 शब्द) 10

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

Discuss the objectives and significance of India's maiden human spaceflight programme- 'Gaganyaan'. Also, enumerate the critical technologies India has developed for Gaganyaan.

(150 words) 10

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2018 को 2022 तक समानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम की बात रखी। जिसके लिए 10 हजार करोड़ का फंड भी आवंटित किया गया है।

गगनयान भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती हुई धमक को प्रदर्शित करता है। जिसके लिए उद्देश्य है।

1) भारत समानव अंतरिक्षयान भेजकर विश्व के चुनिंदा 4 देशों में शामिल होगा।

2) गगनयान के माध्यम से कई प्रकार के शोध एवं अनुसंधान को गति प्राप्त मिलेगी।

3) गगनयान हेतु बहुराष्ट्रीय शक्तिशाली प्रयत्न यान की जड़त होगी। फलतः भारत भविष्य में अपने सम्पूर्ण



drishti



उपग्रह प्रमोचन हेतु स्वतंत्र होगा  
 4) गगनयान के माध्यम से मानसिक तिरणों  
 के प्रभाव का अध्ययन किया जा  
 सकेगा।

उम्मीदवार को इस  
 हाशिये में नहीं लिखना  
 चाहिये।

(Candidate must not  
 write on this margin)

गगनयान को सफुशल अंतरिक्ष  
 अल्पक्षिप्त तकनीकी विकास की  
 आवश्यकता है। जिसमें भारत ने  
 निम्न प्रगति की है।

1) प्रमोचन हेतु GSLV MK-III का  
 निर्माण करना।

2) Crew माड्यूल एंटीमास्किरक रीएन्ट्री  
 प्रोग्राम का विकास ताकि सफुशल  
 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाया  
 जा सके।

3) रियूजेबल लॉच व्हीमल का निर्माण

गगनयान के सफुशल अंतरिक्ष  
 यात्रा हेतु अभी अन्य तकनीकों के  
 विकास पर भी कार्य जारी है।  
 जिसे इसरो द्वारा सफुशल किया  
 जा रहा है।

CARE

6. व्यावहारिक अर्थशास्त्र भारत में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हेतु एक महत्वपूर्ण साधन प्रदान कर सकता है। व्याख्या कीजिये। (150 शब्द) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

Behavioural economics can provide a valuable instrument for socio-economic change in India. Explain. (150 words) 10

इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा में ~~अर्थ~~  
Nudge अर्थात् व्यावहारिक अर्थशास्त्र के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को गति देने हेतु एक विशेष चेंप्टर शामिल किया गया है।

सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हेतु व्यावहारिक अर्थशास्त्र निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण हो सका है।

1) जंग द्रिप्टी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को बढ़ावा देने हेतु आधार का प्रयोग कलत। लीमिज और श्रवण के सप्त्या से निपार।

2) स्वयं भारत अभियान को गति देने हेतु नागरिकों को शांखलप निर्माण हेतु एक मुश्किल धन लक्षि उपलब्ध करना।

3) सुकन्या समृद्धि योजना में अधिक  
 व्याज दर के माध्यम से  
 परिवर्तनात्मक सौच को कमजोर  
 करने का उपास करना

4) 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'  
 'सेल्फी विथ डॉट', 'गुड़ी गुड़ी'  
 बोर्ड में लोगों के व्यवहार  
 परिवर्तन के माध्यम से  
 लिंग संवेदनशीलता को बढ़ा  
 का उपास

5) जल संरक्षण हेतु व्यवहार  
 परिवर्तन हेतु प्रधानमंत्री जी  
 की लोगों से अपील

सारोशतः भारतीय संदर्भ में  
 व्यावहारिक अर्थशास्त्र सामाजिक  
 आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण  
 भूमिका निभा सकता है

उम्मीदवार को इस  
 हाशिये में नहीं लिखना  
 चाहिये।

(Candidate must not  
 write on this margin)

7. आभासी मुद्राओं द्वारा प्रदत्त लाभ विवाद योग्य हो सकते हैं परंतु उनमें अंतर्निहित प्रौद्योगिकी में निश्चित रूप से उज्ज्वल संभावनाएँ समाहित हैं। विवेचना कीजिये। (150 शब्द) 10

The benefits offered by virtual currencies may be debatable but the underlying technology behind them is certainly having bright prospects. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

आभासी मुद्राओं से तात्पर्य उन डिजिटल मुद्राओं से है/ जिनका अस्तित्व सिर्फ डिजिटल रूप तक ही सीमित है। हाल ही में बिटकॉइन जैसी कुछ मुद्राएँ तेजी से उभरी हैं।

1) चूंकि यह किसी बैंकिंग प्रणाली से संबंध नहीं होते हैं। फलतः इनका रेग्यूलेशन (विनियमन) करना असंभव होता है।

2) आभासी मुद्रा के मूल्य में तीव्र गति से होने वाला उतार-चढ़ाव निवेशकों को ~~कम~~ सुभेद्य बनाता है।

3) आभासी मुद्रा पर किसी भी तरह का विनियमन न होने के चलते इसका प्रयोग अवैध गतिविधियों जैसे - तस्करी, मनी लाँड्रिंग, आतंकवादी

कॉडिंग इत्यादि में बढ़ाई

ध्यान रखें कि आभासी मुद्रा में

अंतर्निहित तकनीक में अनेक

संभावनाएँ दिखी हैं।

(1) ब्लॉक चेन तकनीक के माध्यम

से पारदर्शिता, भ्रष्टाचार जैसी

समस्या से निपटा जा सकता है।

2) पीयर टू पीयर के चलते इसकी

सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी रहती

है तथा प्रत्येक ब्लॉक के

आवागमन का हिसाब रहता है।

अतः स्पष्ट है कि आभासी मुद्रा

में उपयुक्त तकनीक विशिष्टकर

पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेहिता

लाने में महत्वपूर्ण भूमिका

निभा सकती है।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

8. विधिक प्रणाली को सुदृढ़ करना भारतीय नीति-निर्माताओं द्वारा किया जा सकने वाला सर्वोत्तम निवेश हो सकता है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Strengthening the legal system may be the best investment Indian policymakers can make. Discuss. (150 words) 10

भारत में न्यायिक प्रणाली में कई व्यापक  
विलंबन की समस्या ने इनके  
समस्याओं को जन्म दिया है। ज्ञातव्य है  
कि वर्तमान में भारतीय न्यायिक  
प्रणाली में 3.18 करोड़ केस लंबित  
हैं।

विधिक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण अिन  
प्रकार से लागू प्रयत्न हो सकता है।

1) सुदृढ़ विधिक प्रणाली तथा नीतियों  
में अस्थिरता की स्थिति समाप्त  
होने से विदेशी निवेशकों के  
लिए सकारात्मक वातावरण का  
निर्माण होगा। फलतः भारतीय  
अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश  
बढ़ेगा तथा रोजगार उत्पन्न होगा।

2) सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था से विवाद  
निपटान की स्थिति में असंमजस्य  
की स्थिति समाप्त होगी। और

उम्मीदवार को इस  
हारा में नहीं लिखना  
चाहिये।  
(Candidate must not  
write on this margin)



drishti



'डेज ऑफ डूइंग बिजनेस' के  
 'कोट्रोल प्रवर्तन' जो कि वर्तमान में  
 अति निम्न स्थिति में है  
 को मजबूती मिलेगी।

उम्मीदवार को इस  
 हाशिये में नहीं लिखना  
 चाहिये।  
 (Candidate must not  
 write on this margin)

9. भारत जैसी आकांक्षी अर्थव्यवस्था सरकार तथा केंद्रीय बैंक के बीच टकराव को सहन नहीं कर सकती है। इस संबंध में हाल की विकास गतिविधियों के संदर्भ में चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

An aspiring economy like India can ill afford a tussle between the government and the central bank. Discuss in the context of recent developments. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस  
मार्ग में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

हाल ही के समय में RBI और  
सरकार के बीच टकराव की स्थिति  
विद्यमान रही। जिसके चलते RBI  
गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नरों द्वारा  
इस्तीफा भी दे दिए गए।

टकराव के मुद्दे

- ① RBI के पास उपस्थित रिजर्व धन  
के प्रयोग हेतु टकराव
- ② धारा 7A के सिफोवपन संबंधी विवाद
- ③ बैंकिंग व्यवस्था में PCA Norms  
ने लेकर विवाद
- ④ NBFC हेतु RBI द्वारा कड़े मानक  
अपनाए जाने संबंधी विवाद
- ⑤ रेपो रेट कम करने संबंधी विवाद

भारत तीव्र गति से संवृद्धि  
करती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था में फलित।  
आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने की

जिम्मेदारी सरकार द्वारा RBI दोनों  
की है

समाधान क्या है

- 1) सरकार और RBI दोनों को सामंजस्य  
पूर्ण दृष्टिकोण बनाकर चलना होगा
- 2) RBI को भी यह समझना होगा  
कि लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही  
लोगों के प्रति है अतः महत्वपूर्ण  
निर्णयों में दोनों की सहमति  
आवश्यक
- 3) सरकार को भी यह समझना होगा  
कि भारत की अर्थव्यवस्था की  
स्थिरता को बनाये रखने में  
RBI को अधिक से अधिक  
स्वतंत्रता दी जाए और उसके  
कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप  
ना किया जाए

सारंशतः समाधान दोनों के सामंजस्य  
पूर्ण दृष्टिकोण में ही विद्यमान है

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

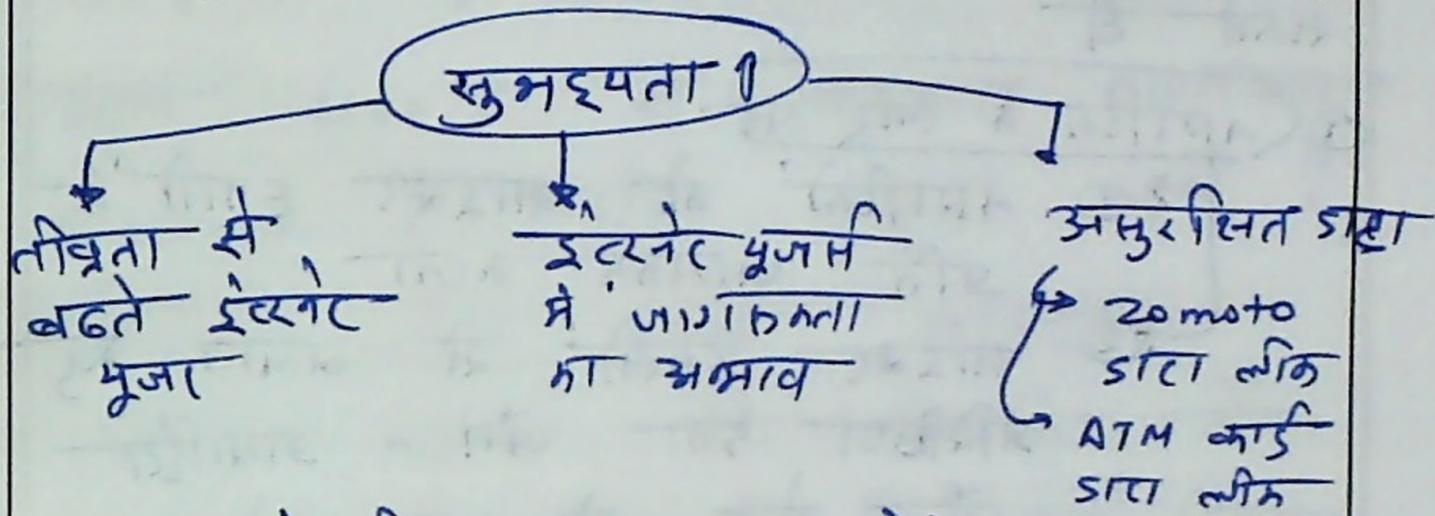
10. संभावित साइबर हमलों के विरुद्ध भारत की तैयारी का मूल्यांकन कीजिये। इस संकट को रोकने के लिये किये जा सकने वाले कुछ संरक्षोपाय सुझाइये। (150 शब्द) 10

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

Evaluate India's preparedness against potential cyber attacks. Suggest measures that should be taken to tackle this threat. (150 words) 10

(Candidate must not  
write on this margin)

हाल ही में भारत की साइबर हमलों के प्रति सुभेद्यता में तीव्रता से वृद्धि हुई है। पनाकार्ड जैसे साइबर हमलों के संदर्भ में इसे देखा जा सकता है।



भारत संभावित साइबर हमलों के प्रति अपनी तैयारी को पुष्ट किता बँधा है।

- ① क्रिटिकल इन्फ्रा की सुरक्षा हेतु NCIIPC का निर्माण करना
- ② साइबर अपराधों हेतु CERT-IN का निर्माण / साथ ही संगठन CERT-IN जैसे FIN-CERT IN का निर्माण किया गया
- ③ राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013

4) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002  
 डा साइबर अटैक से निपटने हेतु  
 नेशनल साइबर ड्राइव को डिनेशन बॉर्डर  
 NCCIT का निर्माण

बढते संकट को रोकने हेतु कुछ  
 अन्य उपाय इस प्रकार दिए जा  
 सकते हैं

① नागरिकों के स्तर पर

→ ① नागरिकों को साइबर हमलों के  
 प्रति जागरूक बना

→ ② साइबर हमलों से बचाव हेतु  
 प्रशिक्षण देना जैसे - अवाइल  
 स्पैम मेस को न खोलना

② सरकार के स्तर पर

→ साइबर हमलों से निपटने हेतु

प्रशिक्षित लोगों की बृहद टीम का  
 निर्माण करना

③ कंपनियों के स्तर पर

→ साइबर हमलों हेतु सीमावित लूपहोल्ड  
 डूबने का उपाय करना

→ जिसमें अधिकतम हेमसी की मदद  
 ली जा सकती है।

उम्मीदवार को इस  
 हाशिये में नहीं लिखना  
 चाहिये।

(Candidate must not  
 write on this margin)

11. पिछले दो दशकों में भारत के उत्कृष्ट विकास के बावजूद निम्न भुगतान तथा वेतन असमानता समावेशी विकास को प्राप्त करने की राह में महत्वपूर्ण बाधाएँ बनी हुई हैं। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

Despite India's outstanding growth in the last two decades, low pay and wage inequality remain serious obstacles towards achieving inclusive growth. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

1991 के आर्थिक सुधारों (LPG सुधार) अपनाने के बाद भारत द्वारा तीव्रता से आर्थिक प्रगति की गयी उदाहरण हेतु 1991 की प्रतिव्यक्ति आय 1100 \$ से बढ़कर लगभग 6600 \$ के करीब पहुँच चुकी है। हालाँकि इसके बावजूद समावेशी विकास की स्थिति में नकारात्मक परिवर्तन भी दर्ज किया गया उदाहरण हेतु आसफेज के रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 1% व्यक्तियों को इस वर्ष कृजित सम्पत्ति में 73% योगदान रहा वहीं निम्न आय वाले निचले 67 करोड़ (50%) लोगों का योगदान मात्र 4% रहा जो

समावेशी विकास सेवकी युवाओं को ही शक्ति है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

### निम्न भुगतान

→ अभी भी अग कानूनों में अस्पष्टता के चलते श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

→ बढ़ती बेरोजगारी भी श्रमिकों को निम्न भुगतान पर कार्य करने से विवश करती है।

### वेतन असमानता

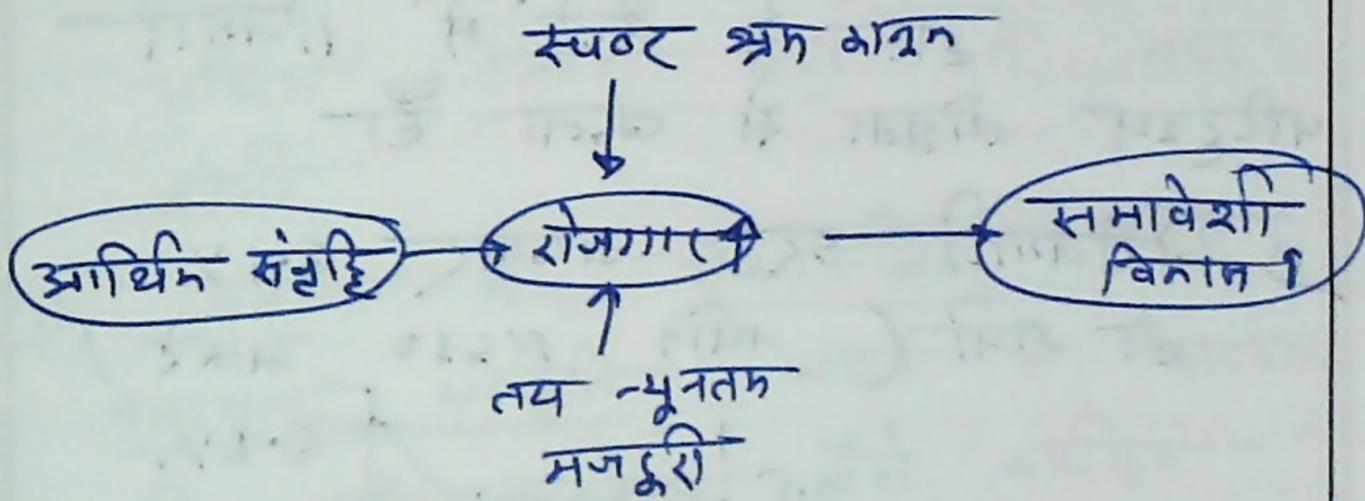
① पुरुष और महिलाओं हेतु वैधानिक समान आय के प्रावधान के बावजूद पुरुषों की आय महिलाओं की आय से औसतन 1.3 गुना अधिक है।

② अकुशल अग जैसे घरेलू काम में संलग्न महिला तथा सिम्प्लीटी गार्ड के रूप में संलग्न पुरुष की आय में बड़ा अंतर

समाधान

① विभिन्न श्रम कानून संबंधी अध्यायों को समाप्त कर श्रम कानूनों का समेकन किया जाए।  
 ध्यातव्य है कि हाल ही में सरकार चार लेबर कोड में सभी श्रम कानूनों को समाविष्ट कर रही है।

② न्यूनतम मजदूरी के एक समान मानक का निर्माण किया जाए।



सारांशतः समावेशी विकास भारत को SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा लिंग असमानता, आय असमानता में (SDG-10) तथा गरीबी उन्मूलन (SDG-1) को खत्म करने हेतु की आवश्यक है।

उम्मीदवार को इस  
 हाशिये में नहीं लिखना  
 चाहिये।  
 (Candidate must not  
 write on this margin)

12. क्या भारत के बदलते रोजगार परिदृश्य में देश के युवाओं को रोजगार इच्छुक से रोजगार सृजक में परिवर्तित करना संभव है? इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए गए हैं? (250 शब्द) 15

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।  
(Candidate must not  
write on this margin)

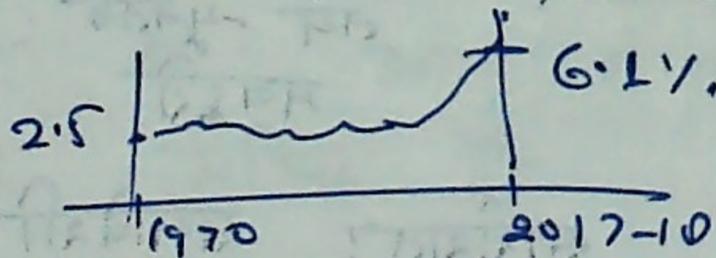
Is it possible to transform India's youth from job seekers to job creators in the changing job scenario in India? What steps have been taken by the government to attain this objective?

(250 words) 15

वर्तमान में भारत जनसाख्यिकी लाभोरी  
से युक्त देश है। अतः बढ़ती जनसंख्या  
हेतु रोजगार उपलब्ध कराना सरकार  
के लिए बड़ी चुनौती है। फलतः  
रोजगार सृजक (Job creators) की  
अत्यधिक जरूरत है।

हाल के दिनों में रोजगार  
परिदृश्य लीप्तता से बदला है।

- 1) बेरोजगारी दर बढ़कर 6.1% हो गयी (नवीन NSSO आंकड़े)



- 2) LFPR (श्रम बह भागीदारी दर) 39% से घटकर 36% के करीब पहुँच चुकी है जिससे महिला LFPR में अत्यधिक पीछे

हुई हैं

२४	2007	2018
LFPR	35%	22%

(W.B  
स्टा)

उम्मीदवार को इस  
होशिये में नहीं लिखना  
सहिये।  
(Candidate must not  
write on this margin)

अतः रोजगार इच्छुक के बजाय रोजगार  
सृजन की जरूरत ~~है~~ है।

1) जाब किलर व्यक्ति के माध्यम  
से कई अन्य लोगों में रोजगार  
मिलता है। फलतः यह बेरोजगारी  
को तीव्रता से कम करेगा

2) दूसरी तरफ GDP की संवृद्धि से  
तीव्रता से बढ़ेगी। जो कि पुनः  
अधिक रोजगार सृजन में मदद  
करेगी

3) समाज में उद्यमशीलता और  
नवाचार संस्कृति बढ़ने से सरकार  
की ~~की~~ मददगा जैसे कार्यक्रम  
चलाकर की बाधता घटेगी।

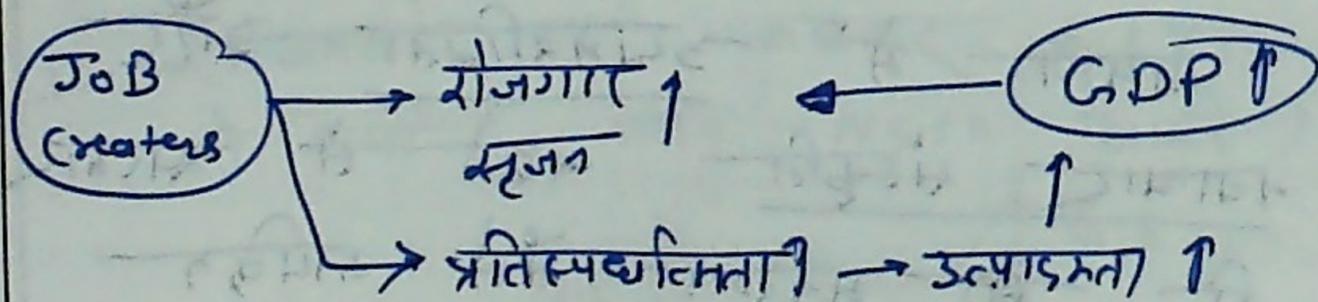
4) अकुशल श्रम से कुशल श्रम  
में संक्रमण होगा। फलतः बदलते  
तकनीकी घाट में (AI, IOT)  
बेरोजगारी के संकट की स्थिति  
धुनतन होगी।

फलतः सरकार और इन ओर  
जागृत है / और तीव्रता से रोजगार  
सृजक को प्रोत्साहित किया जा  
रहा है

उम्मीदवार को इस  
मार्ग में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

- ① स्टार्ट अप इंडिया मिशन के माध्यम से स्टार्ट अप को प्रोत्साहन देना
- ② स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से महिलाओं और वंचित वर्गों की उद्यमशीलता बढ़ाने पर ध्यान
- ③ मुद्रा योजना के माध्यम से स्वरोजगार पर ध्यान



सारांशतः जनसांख्यिकी लाभों का  
जनसांख्यिकी अनिश्चय से बचाने  
हेतु भारत को रोजगार सृजक  
नी अधिक जनता है

13.

वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के संबंध में भारत को कौन-सी नीति तथा शासन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है? इन बाधाओं को संबोधित करने हेतु कुछ विशेष उपायों का सुझाव दीजिये। (250 शब्द) 15

उम्मीदवार को इस कश्चि में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

What are the policy and governance constraints faced by India in doubling farmers' income by 2022? Suggest few specific measures to address these constraints. (250 words) 15

वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की लक्ष्य और विगत वर्ष कृषि की संवृद्धि दर का मात्र 1.4% रहना इस लक्ष्य प्राप्ति की गठिनाईयों को ज्ञाति है।

फलतः आय दोगुना करने में निम्न नीति और शासन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है

1) चूंकि कृषि समवर्ती सूची का विषय है फलतः कृषि पुधारों (जैसे नवीनतम APLM Act - 2017) में राज्यों का सहयोग अपेक्षित है

2) APMC के कारण विपणन संबंधी समस्याएं उत्पन्न बनी हुई हैं प्रत्यक्ष विपणन का अभाव, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति का अभाव अल्पविक्रय विधायियों की उपस्थिति

अनावश्यक कर, जिस इत्यादि के चलते

कृषि किसानों की लाभदायकता अल्पधिक  
कर हुई है।

3) किसानों को बीमा संबंधी दावों  
को प्राप्त करने में अनावश्यक  
समस्याओं का सामना करना  
पड़ रहा है।

4) MSP संबंधी नीतियों का लाभ  
बड़े किसानों और कुछ सीमित संजो  
तक सीमित होना

5) उर्वरक संबंधी नीतियाँ एवं मुफ्त  
बिजली संबंधी नीतियों के चलते  
बढ़ती लवणीयता के कृषि  
उत्पादता को नकारात्मक रूप से  
प्रभावित किया है।

इन बाधाओं को संबन्धित निम्न उपायों  
के माध्यम से हल किया जा  
सकता है।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

① सिंचाई → कृषि सिंचित क्षेत्र का बढ़ावा  
( मध्य प्रदेश - रोह मोडल )  
→ लघु सिंचाई तथा जल का  
कुशलता पूर्ण उपयोग

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।  
(Candidate must not  
write on this margin)

② विपणन → APLM Act को राज्यों द्वारा  
लगाया गया है।  
→ प्रत्यक्ष विपणन की सुविधा दी  
जाए।  
→ सिंगल पाइंट लेवी, सिंगल  
लारसेंस का अपनाना जारी

③ इनपुट कीमत → कृषि स्वास्थ्य मंडि के माध्यम  
से उर्वरकों को कुशल प्रयोग  
अच्छे बजट उपलब्ध कराया

④ बीमा → किसानों के लिए बीमा संबंधी  
विस्तार को अपनाना जारी

⑤ प्रसंस्करण → कृषि प्रसंस्करण उद्योग को  
बढ़ावा दिया जाए।  
→ अनुबंध कृषि के माध्यम से  
किसानों की उपज को प्रसंस्करण  
कम्पनियों को बेचना

⑥ कृषि संबंधी  
गतिविधियों  
को बढ़ावा → पशु पालन } ↑  
→ मत्स्य पालन }  
→ मध्यम स्त्री पालन }

14. 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के उद्देश्य को लक्षित करने के लिये बचत, निवेश एवं निर्यात का एक सुदृढ़ चक्र अतिआवश्यक है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

To achieve the objective of becoming a USD 5 trillion economy, a virtuous cycle of savings, investment and exports is required. Comment. (250 words) 15

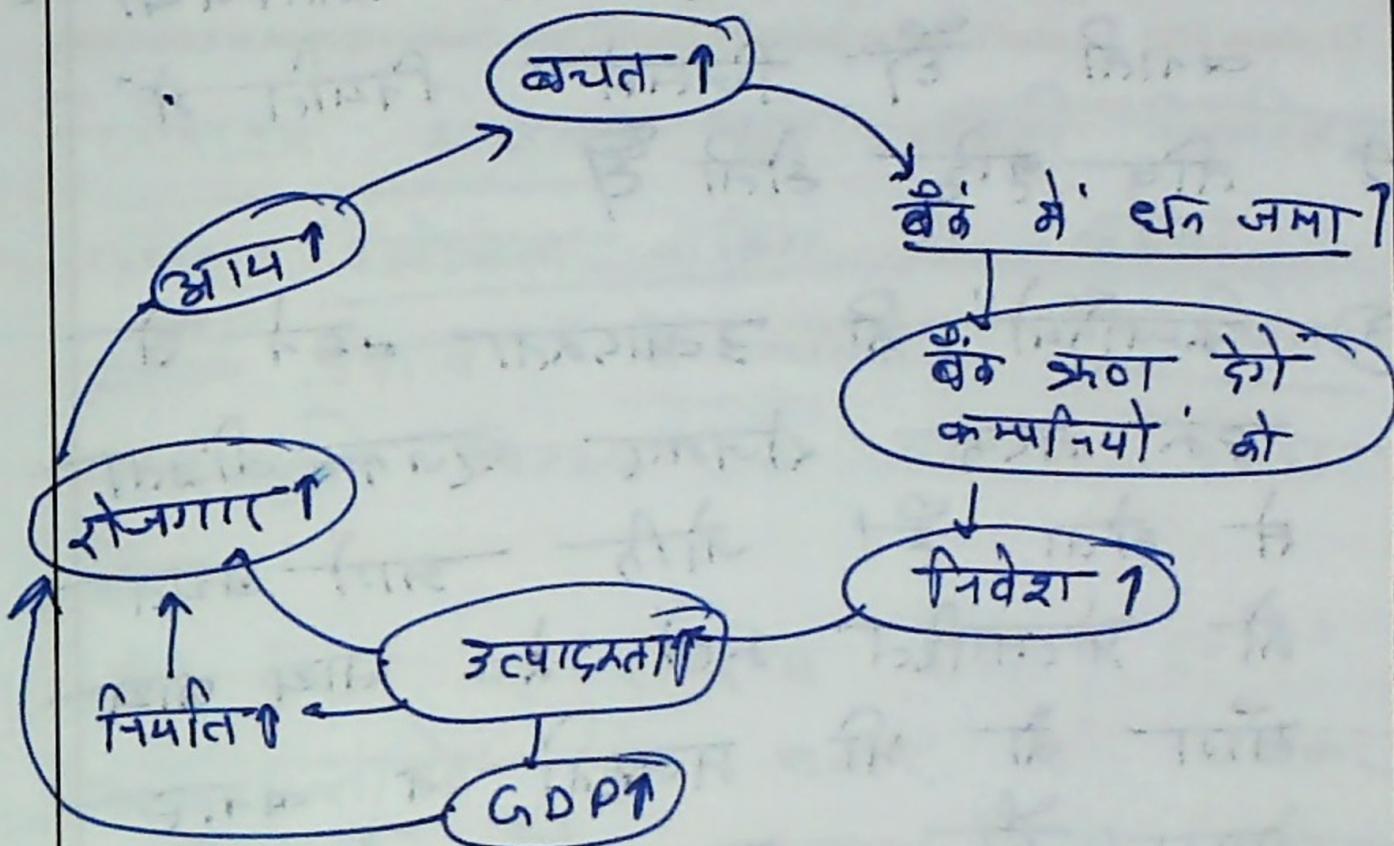
हाल ही में प्रस्तुत बजट में वर्ष 2022 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन \$ की अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी।  
 इसके लिए भारत की GDP में प्रतिवर्ष 8% से अधिक की संवृद्धि की आवश्यकता होगी।

बेहतर संवृद्धि हेतु बचत, निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण हेतु 2005-06 के करीब जब भारतीय अर्थव्यवस्था 9% के करीब संवृद्धि दर से गति कर रही थी तब बचत दर - 35% तथा निवेश दर - 38% के करीब थी। जोकि वर्तमान में बचत दर कमश 29% तथा 32% के करीब पहुँच चुकी है। जिसके

परिणाम स्वरूप - GDP की संवृद्धि पर भी सरकार 6.2% पर मुद्रा चुरी हो

उम्मीदवार को इस हार्शिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)



उपरोक्त चक्र से स्पष्ट है कि बचत और निवेश GDP को तीव्रता से बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं।

1) निवेश बढ़ने से कम्पनियों की उत्पादकता में वृद्धि होती है।  
~~निवेश~~ निवेशित धन का उपयोग बढ़कर मशीनरी के रूप में कम्पनियों की प्रतिस्पर्धामुक्त

में भी वृद्धि करता है

2) वेस्टर प्रतिस्पर्धिता कम्पनियों को

अंतर्द्विप स्तर पर प्रतिस्पर्धी

बनाती है जिससे निर्यात में

अ तीव्र वृद्धि होती है

3) कम्पनियों की उत्पादकता बढ़ने से

एक तरफ रोजगार सृजन वृद्धि

से होता है जो कि आगे बचत

को प्रोत्साहित करने के साथ साथ

माँग को भी मजबूती न बनाए

रखता है यह व घरेलू माँग

भी GDP की वृद्धि में महत्वपूर्ण

भूमिका निभाती है

सारांशतः भारत बचत निवेश निर्यात

की मदद से व द्वितीयक के लक्ष्य

को प्राप्त कर सक्ता है किन्तु हमें

यह ध्यान भी रखना होगा कि यह

वृद्धि समावेशी भी हो।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

15.

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिये। साथ ही किस प्रकार यह नीति भारतीय जैव ईंधन नीति के पूर्व संस्करण का उन्नत प्रारूप है, का परीक्षण भी कीजिये। (250 शब्द) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

Discuss the salient features of the National Policy on Biofuels 2018. Also, examine how this policy is an improvement over the earlier biofuel policy of India. (250 words) 15

जीवाश्म ईंधन पर बढ़ती निर्भरता  
और ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ता  
~~प्रभाव~~ प्रभाव के चलते जैव ईंधन  
महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभरा  
है।  
जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति इन्हीं  
आवश्यकताओं से ध्यान में रखकर  
बनायी गयी है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान  
में भारत में जैव ईंधन का बोयो ग्रीज  
बायो प्रोड्यूस के रूप में मात्र 5% ही  
उपयोग किया जाता है। जबकि  
पूर्व की नीति में इसे 10% निर्धारित  
किया गया था।

प्रतिक्रिया

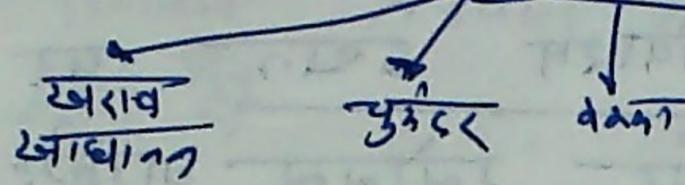
① नयी जैव ईंधन नीति में जैव  
ईंधनों को 2 कर्गों में बांटा  
गया है।

- (i) आधारभूत शिक्षण → 16 बायो डीजल  
→ 20 बायो इथेनॉल
- (ii) उन्नत शिक्षण → 30 बायो इथेनॉल

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

2) जैव शिक्षण के प्रयोग हेतु **करचे माल**  
का विस्तार



3) **अप्रयुक्त छात्रावास**, या बचे हुए  
छात्रावास के प्रयोग हेतु भी अनुमति  
दिनी जाये है ताकि इसके लिए  
अनुमति की आवश्यकता है

4) <sup>जैव</sup> 20 रिफाइनी को प्रोत्साहन  
देने हेतु U.G.F के माध्यम  
से वित्त घोषणा को बहाल  
रिखा जाएगा।

स्पष्ट है कि यह नीति पूर्व संस्करण  
का उन्नत रूप ही है

1) पूर्व की नीति में 'जैव शिक्षण मुख्यतः'  
गना, आधारित था / जिसका  
विस्तार किया गया।

- 2) खाद्यान्न के अल्पचिक्र उत्पादन की स्थिति में प्रयोग की अनुमति पूर्व की नीति से विशिष्ट है
- 3) जैव रिफाइनरी को दिया गया प्रोत्साहन इसकी व्यवहारिता हेतु मददगार साबित होगा।

सारोक्षता, नयी नीति ना केवल हमारे जीवाश्म ईंधन पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को बचाने में सहायक होगी। बल्कि रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण, INDC लक्ष्य प्राप्ति तथा स्वच्छ वायु के दृष्टिकोण से श्री महत्वपूर्ण हैं।

उम्मीदवार को इस  
हाराशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

16. भारतीय शहरों में न्यून-कार्बन परिवहन प्रणाली की आवश्यकता तथा चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इस संबंध में सरकार द्वारा हाल ही में किये गए उपायों का उल्लेख कीजिये। (250 शब्द) 15

Discuss the necessity and challenges of a low-carbon transport system in Indian cities.

Mention the recent measures taken by the government in this regard. (250 words) 15

बढ़ते वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने न्यून कार्बन परिवहन प्रणाली की आवश्यकता को बढ़ाया है। इसी आवश्यकता को देखते हुए भारतीय सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन को तीव्रता से प्रमोट किया जा रहा है।

भारतीय शहरों में न्यून कार्बन प्रणाली की आवश्यकता

- ① WHO की रिपोर्ट के अनुसार 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 14 शहर भारत के हैं।
- ② वाहनों से उत्सर्जित वायु प्रदूषण के चलते प्रतिवर्ष 2 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है।
- ③ दूरी तरह इससे स्वास्थ्य पर सकार और परिवार का खर्च बढ़ता है।

4) उत्पादकता → वायु प्रदूषण प्रक्रिया की उत्पादकता को सीमित करता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।  
(Candidate must not write on this margin)

5) INDC लक्ष्य → न्यून कार्बन प्रणाली INDC लक्ष्य प्राप्त में मददगात होगी।

इसके बावजूद इसमें कुछ पुनर्निर्माण की हुई है।

1) इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त बैटरी हेतु कच्चे माल (लीथियम) की कमी → जो कि अनावश्यक रूप से विदेशी देशों (चीन) पर निर्भरता बढ़ाती है।

2) चार्लिंग इकाई वर्तमान में चार्लिंग इकाई की स्थिति सुदृढ़ नहीं है। यहाँ पर यह भी है कि चार्लिंग इकाई हेतु उत्पादित बिजली नवीकरणीय साधनों से उत्पादित की जाये है या जैद नवीकरणीय साधनों से।

3) मंहगे इलेक्ट्रिक वाहन



~~सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को लगातार बढ़ावा देने हेतु प्रयास रत है~~

1) इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु FAME योजना - फोस्टर एडिप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हायब्रिड व्हीकल

2) इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु नेशनल मोबिलिटी मिशन

3) पिछले महिने सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST घटकर 5% कर दिया।

सारांशतः SDG लक्ष्यों विशेष

SDG-13 (पदविरोध) SDG-3 (गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य) को प्राप्त करने

के तथा SDG-7 (सतत ऊर्जा)

को प्राप्त करने में न्यून कार्बन

परिवहन प्रणाली महत्वपूर्ण साबित

हो सकती है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

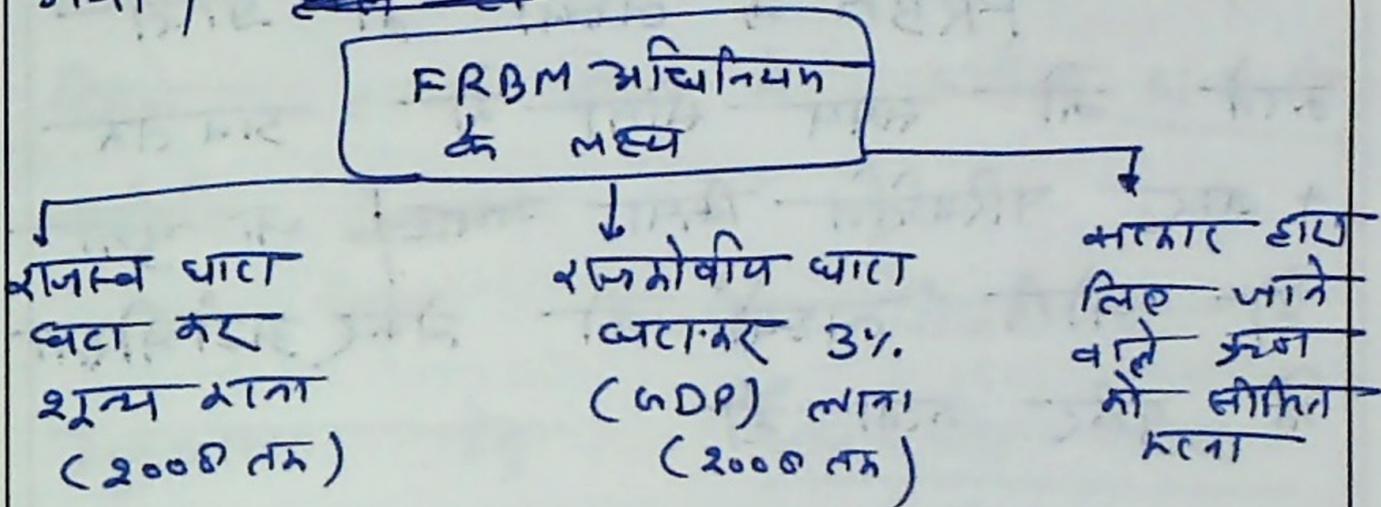
17. वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम के क्रियान्वयन से भारतीय अर्थव्यवस्था में केवल शाब्दिक रूप से राजकोषीय सावधानी देखने को मिली, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

Enactment of Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act has brought the Indian economy on the path of fiscal prudence only in letter but not in spirit. Critically analyse. (250 words) 15

राजकोषीय अनुशासन और सुदृढ़ता हेतु 2003 में FRBM अधिनियम बनाया गया।



वस्तुतः FRBM अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा सरकार पर राजकोषीय अनुशासन को अपनाने का प्रयास किया गया।

इसी के चलते राजकोषीय घाटे को 2008 तक व्यतार 3% (GDP) पर लाने पर राजस्व व्यय को शून्य लाने की बात की गयी।

किल्ले वर्तमान (2019) हो जाने  
 के बावजूद के इसका रिपोर्टिंग नहीं  
 हो पाया है - इसी का प्रतीक  
 है कि अभी भी राजकोषीय घाटा  
 3.4% तथा राजस्व घाटा 2.2% का  
 हुआ है

FRBM के लक्ष्यों को प्राप्त  
 करने की समय सीमा में अब तक  
 4 बार परिवर्तित किया गया है जो चुका  
 है जो कि लक्ष्यों को लेकर अर्गुमीरता  
 में पुष्टि करता है

यही कारण था कि 2008 की  
 मंडी से निपटने हेतु पुनः राजकोषीय  
 घाटा 6% के करीब मंजूर किया गया

राजकोषीय अनुशासन भारत के  
 लिए बहुत जरूरी है क्योंकि राजकोषीय  
 अनुशासन का केवल केडर रेटिंग  
 एजेंसी को भारत की सोवरेन रेटिंग

उम्मीदवार को इस  
 हाशिये में नहीं लिखना  
 चाहिये।

(Candidate must not  
 write on this margin)

क अर्दी देने पर भजबूर करता है  
कलिक इससे विदेशी निवेश आकर्षित  
होता है। तथा अर्थव्यवस्था में  
स्थिरता बनी रहती है।

देखते हुए राजकोषीय अनुशासन की  
प्राप्ति पर बल दिया जा रहा है  
जिससे हाल ही में वर्ल्ड N.K सिंह  
समिति के रूप में देखा जा  
सकता है। जिले राजकोषीय  
अनुशासन हेतु राजकोषीय पत्रिका  
बनाने की भी सिफारिश की।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।  
(Candidate must not  
write on this margin)

18. वामपंथी अतिवाद (एल.डब्ल्यू.ई.) राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिये एक बड़ा संकट बना हुआ है। सुस्पष्ट कीजिये। साथ ही इस मुद्दे के समाधान हेतु सरकार द्वारा किये गए विभिन्न उपायों की भी विवेचना कीजिये। (250 शब्द) 15

Left-Wing Extremism (LWE) remains a major threat to the internal security of the country. Elucidate. Also, discuss various measures taken by the government for addressing this issue. (250 words) 15

हाल की वामपंथी अतिवादी घटनाएँ सुकुमा अटैक, बस्तर अटैक यह ज्ञाता है कि यह राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा हेतु बड़ा संकट घटित हुआ है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा भी नक्सलवाद को आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी धमकी मानी थी।

वामपंथ अतिवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा हेतु संकट

1) अभी भी एक तिहाई जिलों में किसी न किसी रूप में वामपंथ अतिवाद का प्रभाव है।

2) घटनाओं की संख्या घटी है किन्तु अभी भी नक्सलीकरणों द्वारा बड़े हमले (सुकुमा) प्रयोजित किए गए हैं।

3) वामपंथी उग्रवादियों को चिन जैसे बाह्य कारकों से दृष्टिगत, धन इत्यादि की मदद; भारत की आंतरिक सुरक्षा को और सुभेद्य बनाती है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।  
(Candidate must not write on this margin)

4) विकास - 'बकसलवार प्रभावित क्षेत्रों में' विकासोन्मुख गतिविधियों का अभाव वहाँ की जनता को नकसली गुर में शामिल होने हेतु सुभेद्य बनाता है।

अतः भारत सरकार लगातार वामपंथी अतिवाद को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। उसी का परिणाम है कि वामपंथी उग्रवाद में तीव्रता से कमी आई है।

विकासोन्मुख उपाय

- 1) कौशल विकास → ~~स्त्री~~ रोजगारी योजना के माध्यम से
- 2) अवसंरचना विकास → शिक्षा स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने का उपाय
- 3) FRA-2006 PESA वाहन → इनके कुशल नियोजन के माध्यम से असंतोष दूर करने का उपाय

\* आत्मसमर्पण व पुनर्वासि की नीति

सुरक्षात्मक उपाय

समाधान  
रवनीति

नक्सलवादी घटनाओं के  
प्रति सुरक्ष कार्यवाही

वित्त तक पहुच में  
सीमित करना

सुरक्षा बलों  
का आधुनिकीकरण

बेहतर एचिभाट

माइन प्रोटेक्टर्स वाहन

स्पेशल कमांडो बल

~~संवेदन~~

स्पष्ट है कि एक तर्फ हमें नक्सलवाद  
के विरुद्ध तबोर कार्यवाही की आवश्यकता  
है तो वहीं दूसरी तर्फ वहाँ  
की विशेष जनता तक विकासत्मक  
गतिविधियों का लाभ पहुचाने  
सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना  
होगा / तभी हम नक्सलवाद जैसी  
समस्या का समूल नाश कर  
सकेगे।

19. भारतीय रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण कई संकटों का हल प्रदान कर सकता है। हालाँकि राह उतनी आसान नहीं है जितनी प्रतीत होती है। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

Indigenising the Indian defence sector can address multiple woes, however road is not as easy as it seems. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

किसी भी देश की सुरक्षा हेतु रक्षा क्षेत्र का मजबूत होना अत्यधिक आवश्यक है। यूँ तो भारतीय रक्षा क्षेत्र समूह माना जाता है किन्तु इसकी समृद्धता विदेशी आपात पर आधारित है।

व्यातक्य है कि भारतीय रक्षा क्षेत्र के अधिकांश उपकरण, एथिपार, विमान वाहक पोत, फाइटर प्लेन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पुडुकोनी या तो आयातित हैं या विदेशी सहायता की मदद से बनाये गए हैं।

भारतीय रक्षा क्षेत्र का मात्र 10% हिस्सा भारतीय कंपनियों द्वारा विनिर्मित है।

स्वदेशीकरण से आवश्यकता क्यों

- ① विदेशी निर्भरता भारत के रक्षा क्षेत्र में लुभेय बनाता है।
- ② आयात पर होने वाले बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय को बचाएगा।
- ③ भारतीय कंपनियों (HAL) की अक्षमता, और गैर प्रतिस्पर्धकता।
- ④ युद्ध के समय विदेशी असहयोग की स्थिति बन सकती है। उपरोक्त हेतु कारणों से युद्ध के समय अमेरिका की GPS तकनीक पर हमारी निर्भरता से हमें कमजोर स्थिति में पहुँचाया था।

~~यह स्पष्ट है कि रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण वांछित तो है किन्तु यह राह उतनी आसान नहीं~~

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

1) भारतीय कंपनियों के पास उच्च स्तरीय तकनीक का अभाव

↳ साफेल, विमानकी एक पोत, परमाणु

पनडुब्बी, झुंझारि बनाने में

भारतीय कंपनियों की असमर्थता

2) अगर बनाने का प्रयास भी किया

जाता है तो लागत अत्यधिक

आएगी / फलतः आयात ही

~~प्रयोज्य~~ करना ही अधिक

लाभदायक सिद्ध हो जाता है

3) रक्षा विनिर्माण में प्रतिस्पर्धिता

वातावरण का अभाव

स्वयं ही भारतीय रक्षा भंड

का स्वदेशीकरण अविष्य की अनिवार्य

आवश्यकता है / जिसके अधिक

समय तक टालकर रखना ना देव

हमारी खिंदगी निश्चिता को बहालगा

बल्कि हमारी सुरक्षात्मक पहलू

को भी कमजोर होगा।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

20. भारत में विधिक तथा संस्थागत तंत्र मौजूद होने के बावजूद नीति निर्माताओं के लिये आपदा प्रबंधन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द) 15

Despite legal and institutional mechanisms in place, disaster management continues to pose a daunting challenge for policymakers in India. Critically evaluate. (250 words) 15

भारत आपदा हेतु अत्यधिक संवेदनशील देश है। उदाहरण हेतु भारत की तटीय सीमा इसे चक्रवात, सुनामी हेतु प्रभेद्य तथा 68% भारतीय क्षेत्र सूखा हेतु प्रभेद्य तथा 12% क्षेत्र बाढ़ हेतु प्रभेद्य हैं।

फलतः आपदा प्रबंधन की दृष्टि से भण्डित होगा भारत के लिए अनिवार्य है

भारत में विधिक तंत्र

- ① आपदा प्रबंधन कानून - 2005
- ② आपदा प्रबंधन नीति - 2009
- ③ आपदा प्रबंधन नियम - 2018
- ④ हाल ही में सेंडाई फ्रेमवर्क संबंधी प्रावधानों को अपनाया गया।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

संख्यागत तंत्र की उपस्थिति भी भारत में छूट ही जैसा

आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत  
केंद्रीय स्तर पर NDMA, राज्य स्तर पर SDMA तथा स्थानीय स्तर पर DDMA की स्थापना की गयी है

आपदा के समय प्रबंधन में मदद हेतु NDRF, SDRF (फोर्स) की उपस्थिति

आपदा के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया हेतु नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स

की भी व्यवस्था

इसके बावजूद आपदा प्रबंधन पूर्णतया सही

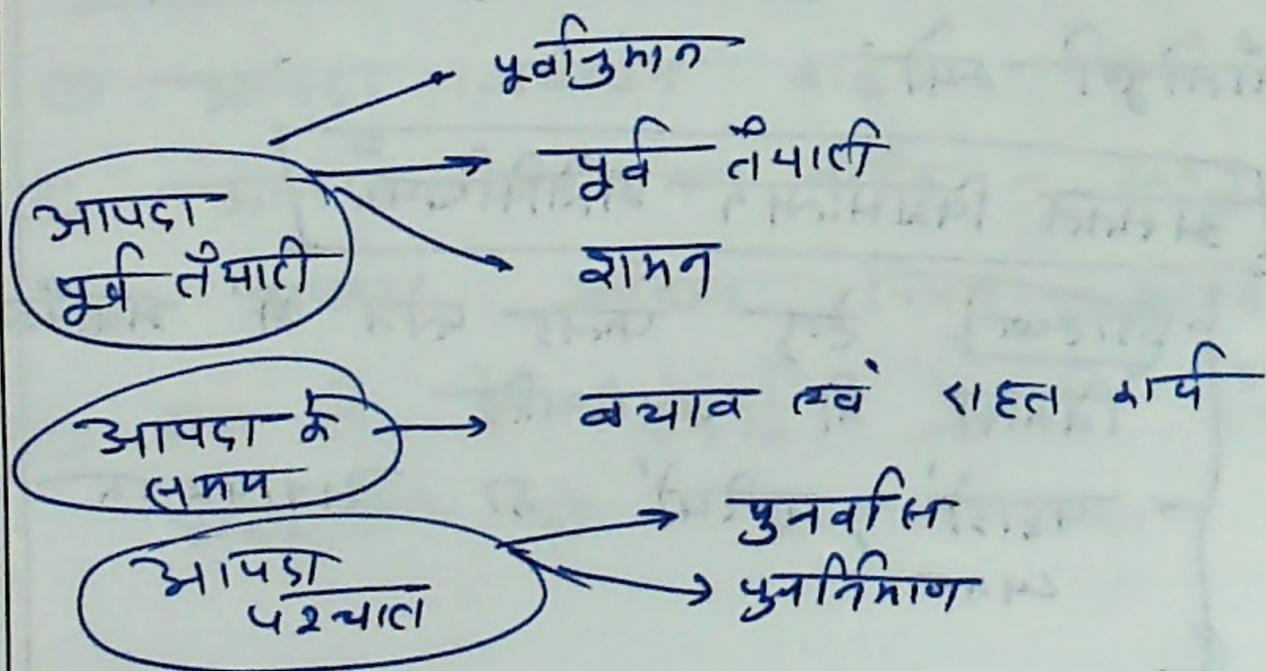
असतत विकासवादी गतिविधियाँ

उदाहरण हेतु फलास क्षेत्र में अवलंबन विकास की उपस्थिति पहाड़ों, नदियों का अनावश्यक धरण

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

- ② आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना का अभाव
- ③ शमन हेतु आपदा मैपिंग, इत्यादि का अभाव
- 4) आपदा पूर्वानुमान में कमी  
 हालांकि इन 'पूर्वानुमान' के बावजूद भी भारत आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है 35।8% तक  
 1) हाल ही में आए फानी चक्रवात से यूनतम क्षति  
 2) नेपाल में भूकंप प्रबंधन में सहयोग



उम्मीदवार को इस  
 हाशिये में नहीं लिख  
 चाहिये।  
 (Candidate must n  
 write on this marg